Speaking at Press Conference, Lucknow

February 09, 2017

प्रदेश अँधेरे में ही डूबा हुआ है बिजली के ही क्षेत्र में नहीं लेकिन कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी | पिछली बार जब आया था आप से चर्चा करने तब राम नारायण साहू जी और मैं श्री शरण साहू जी के घर पे गए थे | पहले आयूष साहू फिर शरण साहू जी, परिवार में दो दो लोगों को बहुत ही घिनौने तरीके से मौत के घाट उतार दिया था गुंडों ने | और उनके घर जब गया था तो बहुत पीड़ा हुई थी, चिंता हुई थी किस प्रकार की कानून व्यवस्था इस प्रदेश में है | आज मुझे मालूम पड़ा कि हाई कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है और कल जब हाई कोर्ट इस विषय की गंभीरता से चर्चा कर रहा था तो हाई कोर्ट ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बहुत सख्ती से कहा और कहा कि सरकार की लापरवाई से गई शरण साहू जी की जान | यह भी सवाल पूछे कि क्यों उनको सुरक्षा नहीं दी गई, क्यों लाइसेंस नहीं दिया गया, क्यों न उनको परिवार को मुआवजा दिया जाये |

और वास्तव में यह परिस्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही दुखदाई होती जा रही है | यहाँ से अगले दिन निर्धारित था पहले से हमारे कार्यक्रम तय.... निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से मुझे सहारनपुर जाना था वहां पे भी एक पनीर और दूध के व्यापारी अरोरा जी की बहुत ही गन्दी तरीके से हत्या की गयी थी | उनके घर जाके उनके दोनों छोटे छोटे बच्चों को मिलने का मौका मिला, बहुत ही परेशान थे, बहुत भय में थे | ग्यारवीं में पढ़ती हुई उनकी छोटी लड़की ने हाथ पकड़ के मुझसे पूछा कि मेरे पिताजी को उतने बुरी तरीके से क्यों मारा | और यही उम्मीद जताई कि आरोपियों को पकड़ा जायेगा, आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, उनको सुरक्षा दी जाएगी परिवार वालों को |

और फिर अगले दिन 5 तारीख को मुझे मेरठ जाना था, मेरठ में भी 23 वर्षीय अभिषेक वर्मा को जिस प्रकार से गुंडों ने मारा, गोलियों से भूंद दिया, उनके पिताजी और तीन और व्यक्ति अभी भी अस्पताल में है, आरोपी पकडे नहीं गए | इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जिस प्रकार से व्यापारी, जिस प्रकार से सामान्य नागरिक, महिलाएं भय में हैं, डर में रहती हैं उत्तर प्रदेश में | उसी बीच जब खबर मिलती है कि जो हाथरस में हाल ही में सपा-बसपा के बीच झगडा हुआ उसमें जो आरोपी एक विधायक था और वह विधायक फरार है | लेकिन अभी अभी कोई टेलीविज़न चैनल पे पता चला कि मुख्यमंत्री के मंच पे वह आरोपी शामिल था | अब जो आरोपी को पुलिस इस राज्य की पकड़ नहीं पा रही है वह Z-security पाने वाले सीएम के मंच पे हो और पुलिस कोई कार्रवाई न कर पाए, मैं समझता हूँ बहुत ही स्पष्ट होता जा रहा है कि यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो गयी है, शायद पुलिस भी इसमें मिली हुई है | और इसलिए आज यूपी का अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है और मैं आज के लिए अखिलेश यादव जी और सपा से यह सवाल करना चाहूँगा कि कितने आरोपी जेल से फरार हो चुके हैं और वापिस नहीं आये हैं?

मैं समझता हूँ अगर CM, Chief Minister, अखिलेश यादव जी में थोड़ी भी नैतिकता हो तो वह जनता को इस सवाल का जवाब देंगे, जनता को बताएँगे कि आरोपी जेल से फरार होते हैं, उनको कभी वापिस लाने की चेष्टा नहीं की जाती है, कैसे फरार होते हैं, कानून क्या कर रहा है? साथ ही साथ मैंने प्रदेश को अँधेरे में रहने की बात की, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आने के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले विद्युत् क्षेत्र में किये गए | आप सभी जानते हैं कि यह जो क्षेत्र हैं कोयला और बिजली, यह दोनों क्षेत्र लगभग 68 वर्ष तक

shortages में रहते थे, इसकी कमी रहती थी, बिजली भी कम रहती थी, कोयला भी कम रहता था |

जब मैं कोयला मंत्री बना तब आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासन के समय की और जब यूपीए-1 थी तब तो सपा भी उनके समर्थन में थी | जो 1,86,000 करोड़ रुपये का कोयले का घोटाला coal के mines के आवंटन में हुआ और साथ ही साथ कोयले का उत्पादन भी बहुत कम रहता था देश में तो लगातार कोयले की कमी रहती थी, दो-तिहाई बिजली घर देश के बहुत कम कोयले से झूझ रहे थे, 7 दिन से भी कम coal stock था | वास्तव में उत्तर प्रदेश को भी कोयले की कमी रहती थी और कई बार उत्तर प्रदेश सरकार हमारे पास यह विषय लाती थी जब मैं नया नया मंत्री बना कि कोयला ज़रा और भेजिए |

मुझे आपको बताते हुए ख़ुशी होती है कि केंद्र सरकार ने कोयले का उत्पादन भी इतना बढाया कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी thermal plant, बिजली घर एक भी नहीं है और वास्तव में पूरे देश में एक भी बिजली घर नहीं है जहाँ पे critical stock हो या कोयले की कमी हो, जिसके कारण जितनी बिजली उत्तर प्रदेश को चाहिए उतनी चौबीसों घंटे उपलब्ध हो सकती है | साथ ही साथ हमने कोयले का बहुत बड़ा ब्लाक सहारपुर-जामरपानी कोयले की खदान जिसमें 52 करोड़ टन कोयला है, 52 crore tonnes कोयले का भंडार है वह हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् उत्पादन निगम को दिया कि उसमें से बिजली के लिए जो कोयला लगता है उत्तर प्रदेश को वह खुद आत्मनिर्भर हो सके | उसके इलावा हमने कई बिजली घरों को bridge linkages sanction करी उत्तर प्रदेश में और जो चारों बिजली घर हैं उत्तर प्रदेश के जिनको critical stock होता था June 2014 में, आज के दिन वह 8,800 MW के चारों बिजली घर में पर्याप्त मात्रा में कोयला है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है | इसके इलावा आप सब जानते हैं और आप विद्युत् प्रवाह

में देखते रहते होंगे कि जितनी बिजली उत्तर प्रदेश को चाहिए वह चौबीसों घंटे उत्तर प्रदेश को उपलब्ध है पॉवर एक्सचेंज से, जब वह चाहें पॉवर एक्सचेंज से बिजली खरीद सकते हैं |

अभी के समय भी जब मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ 3.57 बजे हैं अभी, 2.85 रुपये में सिर्फ जितनी बिजली उत्तर प्रदेश चाहे उतनी खरीद सकती है पॉवर एक्सचेंज से | और वास्तव स्थिति यह है कि प्रदेश में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली पर्याप्त मिलती नहीं है | मैं जिधर जाता हूँ और मैं पूरे प्रदेश में कई जगह गया सहारनपुर गया, आगरा में था कल, उसके पहले मेरठ गया, नोएडा गया, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ सबसे बड़ी शिकायत यह मिलती है कि मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा कर दी हाँ यह अलग बात है कि साढ़े चार वर्ष विलंभ से की, 2012 का घोषणा पत्र था लेकिन दिवाली 2016 में यह घोषणा की कि चौबीस घंटे बिजली देंगे लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि सभी जगह शिकायत मिलती है कि बिजली भी नहीं मिलती, मिलती है तो आती जाती है, पॉवर कट बार बार होता रहता है | लेकिन राज्य सरकार केंद्र को लिखके देती है कि हमारे यहाँ पे बिजली की कमी भी शून्य है और उसके कारण पॉवर एक्सचेंज में 2.85 रुपये पे मिलने के बावजूद वह बिजली खरीदती नहीं है |

हमारी सरकार आने के बाद ग्रामीण विद्युतीकरण और शहरी सुधिकरण के लिए लगभग डेढ़ गुनाह अधिक पैसा आवंटन किया गया दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और IPDS के द्वारा लेकिन जो काम में प्रगति और गति होनी चाहिए थी दुर्भाग्य से वह हमें मिलती नहीं है | यह एक मात्र प्रदेश है पूरे देश में जिसने अभी तक 24/7 Power For All, यह जो करार केंद्र सरकार ने देश के हर एक राज्य के साथ किया कि हर घर तक बिजली पहुंचे और हर व्यक्ति को, हर घर को 24/7 बिजली मिले यह Power For All डॉक्यूमेंट देश के 28 राज्यों ने और हर

Union Territory ने किया है | मात्र उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है जिसने यह sign नहीं किया है और मुझे लगता है इसमें उनकी इच्छा शक्ति दिखती है कि उनकी इच्छा ही नहीं है कि हर गरीब के घर में बिजली पहुंचे, हर घर को चौबीसों घंटे बिजली मिले | और मुझे आपको बहुत खेद है बताते हुए कि आज भी लगभग 3 करोड़ घर हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से 1 करोड़ 7 लाख घर ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है, 3 करोड़ में से 1 करोड़ 7 लाख | और मैं कागज़ लाया हूँ जिसमें हमें उत्तर प्रदेश की सरकार की DISCOMS से लिखित रूप में आया है कि लगभग हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने के लिए पर्याप्त राशि केंद्र सरकार ने आवंटन की है, हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली देने के लिए पर्याप्त राशि आज राज्य सरकार को केंद्र ने उपलब्ध करवादी है |

यहाँ पे नए प्रोजेक्ट लगने चाहिए, एक प्रोजेक्ट मेरे संज्ञान में आया घाटमपुर का जिसमें सपा सरकार और कांग्रेस की केंद्र सरकार और उस समय के कांग्रेस के कोयला मंत्री ने उद्घाटन भी कर दिया था घाटमपुर में | लेकिन मज्जेदार बात यह थी कि जून 2012 में उद्घाटन तो कर दिया, भूमि पूजा तो कर दी जिसमें जैसवाल जी और अखिलेश यादव जी और इनका गठबंधन तो वास्तव में दो भ्रष्टाचारी पार्टियों का, दो भ्रष्टाचारी नेताओं का और दो विकास-विरोधी नेताओं का गठबंधन है वह उनके केंद्र के काम और राज्य सरकार के कामों से दर्शाता है |लेकिन यह प्रोजेक्ट का ना PIB approval हुआ था, ना इसके लिए राशि आवंटन हुई थी, ना इसके लिए सब clearances मिले थे लेकिन भूमि पूजा जल्दबाजी में करके उसके बाद दो वर्ष तक कुछ काम नहीं हुआ | मोदी जी की सरकार आने के बाद उसमें गति लाई गई, पूरी ज़मीन का acquisition हो गया है, पूरे 828 hectare ज़मीन ली गयी सरकार के द्वारा, Project Investment Board (PIB) का clearance लिया, 17,237 करोड़ रुपये का जो 8 फरवरी, 2016 को मिला, project sanction

हुआ 27 जुलाई, 2016 को government of India द्वारा, कोयले का letter of assurance मिला 4 अगस्त 2016 को और पछ्वाडा साउथ coal block भी आवंटन किया झारखंड में जिसमें लगभग पूरा यह जो यह प्रोजेक्ट है Neyveli Uttar Pradesh Power Limited का घाटमपुर का, 1980 MW का इसके लिए पर्याप्त कोयला है, यह एक अलग ब्लाक, दूसरा ब्लाक उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया |

इस प्रकार से मोदी जी की सरकार ने एक एक प्रोजेक्ट को तेज़ गति मिले इस काम पे बल दिया | अब नोएडा के नजदीक भी एक प्रोजेक्ट की ज़मीन को उपलब्ध कर दिया गया है, ज़मीन ली गयी है उसमें भी अभी हम काम तेज़ी से करना शुरू कर दिया है | नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत प्रयासों के बाद एक solar park का proposal राज्य सरकार से आया 600 MW का जिसको हमने तुरंत ..... किया | मैं चाहता हूँ और हमारे संकल्प पत्र में हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जगह बंजर ज़मीन है, इतनी जगाएँ हैं जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ हम सौर ऊर्जा को तेज़ी से बढ़ावा दे सकते हैं | साथ ही साथ rooftop solar के लिए भी हमने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार गति देगी, उसको तेज़ी से हर घर तक पहुँचाने के लिए प्रयत्नशील रहेगी |

वैसे आंकड़े जब मैं देखता हूँ तो हमारी सरकार ने 15 अगस्त, 2015 को जो घोषणा की कि जितने गाँव विद्युत् से जोड़े नहीं गए हैं, unelectrified रहे हैं उसको अब केंद्र सरकार निगरानी करके तेज़ गति देगी | आपको जानके आश्चर्य होगा कि जहाँ 2009-10 से लेके 2014-15 तक बहुत कम गाँव में बिजली, नए गाँव में बिजली पहुँचती थी, 2009-10 में मात्र 56 गाँव, 2010-11 में 23 गाँव, 2011-12 में 0 नए गाँव, और यह तीनों बसपा के राज के समय के | लेकिन जनता ने निकाल के सपा को राज दिया तो 2012-13 में भी 3 ही गाँव, 2013-14 में 0 और 2014-15 में 59 |

इस गति पे यहाँ पे काम होता था | जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बल दिया कि इसको काम को एकदम समय सीमा पे किया जाये तब केंद्र सरकार के प्रयासों से और हमारे दबाव में राज्य सरकार को काम को गति देनी पड़ी और तब जाके 1305 गावों में पिछले वर्ष हम बिजली पहुंचा पाए जिसके लिए हमने ग्रामीण विद्युतीकरण अभियंता दिल्ली से भेजके हर डिस्ट्रिक्ट में लगाये और इस काम में गति दी | दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश में जो पॉवर कट्स होते हैं, उत्तर प्रदेश में जो बिजली मिलती है और उत्तर प्रदेश में जो बिजली की चोरी होती है या बिजली का losses होते हैं, AT&C losses वह पूरे देश के सामने बहुत ही अधिक है | उदाहरण के लिए अगस्त 2016 के आंकड़े मिले क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश ने आंकड़े ही डालना बंद कर दिया ऊर्जा अप्प के ऊपर, पर अगस्त 2016 में दो गुनाह power cut उत्तर प्रदेश में होता था बाकी देश के average के सामने, लगभग 7 गुनाह power cut होता था उत्तर प्रदेश में बाकी देश के average के सामने |

और अन्य अन्य योजनाएँ देने के बावजूद दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश के काम में बहुत ही धीमी गति रही है और अब भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि हमारी जो नयी सरकार अगले महीने पूर्ण बहुमत, दो-तिहाई बहुमत से उत्तर प्रदेश में आएगी वह सरकार प्रदेश में हर घर तक बिजली पहुंचाएगी, हर गरीब के घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जायेगा, हर गरीब को पहले 100 unit तक मात्र 3 रुपये में बिजली चौबीस घंटे मिलेगी इसको सुनिश्चित किया जायेगा | किसानों को सस्ते दर पे पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जाएगी और एक विशेष घोषणा कि हर किसान और आप जानते हैं किसानों के पास बाबा आदम के ज़माने के पुराने पंप हैं, कई बार चलते हैं कई बार नहीं चलते हैं | आधे किसान तो electrician बन गए हैं उन पुम्पों को rewind कर करके जिसमें खर्चा भी बहुत करना पड़ता है|

हमने तय किया है हर किसान के पुराने पंप को एक energy efficient नए पंप के साथ replace किया जायेगा मुफ्त में, किसानों को मुफ्त में एक नया energy efficient पंप ऐसा दिया जायेगा जिसमें SMS द्वारा किसान on भी कर सके अपने घर पे, अपने घर बैठगे SMS द्वारा व्यक्ति उसको on कर सकेगा, उस पंप में एक flow meter होगा जो कितना पानी निकला उसको measure करके alarm देगा मोबाइल के ऊपर कि आपने जितना पानी निर्धारित किया था उतना अब हो चूका है तो SMS द्वारा ही घर बैठे अपनी घाट पे किसान उस पंप को बंद भी कर पायेगा | यह सहूलियत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संकल्प पत्र में इसको हमने घोषणा भी की है, आपके शायद ध्यान में रह गयी हो यह बात लेकिन मैं चाहूँगा तो यह बात को आप हर किसान तक, हर प्रदेश के हर कोने तक पहुंचाएं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्युत् क्षेत्र में बुनयादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ के पूरे विद्युतीकरण के काम को कैसे तेज़ गति से और अच्छी गुणवत्ता वाले काम को करने के लिए आगे काम करेगी |

मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा | जब यहाँ पे संकट आया काम की गुणवत्ता ख़राब बताई जा रही थी, जनता बड़ी परेशान थी तब हमने यहाँ की एक audit कराई और यह audit normal course में 3-tier quality assurance mechanism है ग्रामीण विद्युतीकरण का जो किया जाता है | आप सबको जानके हैरानी होगी और यह आंकड़े एकदम आश्चर्यजनक हैं कि जब हमने यह audit कराई तो कितने defect निकले उत्तर प्रदेश के विद्युतीकरण के काम में और मैं सिर्फ ग्रामीण विद्युतीकरण के काम की बोलूँगा | 89,841 quality defects मात्र उत्तर प्रदेश में, लगभग 90,000 quality defects और यह 11वीं plan phase-II और 12वीं plan के जो काम चल रहे हैं यह उसके quality defects, 90,000 | हर मेरे ऑफिस ने उन सब रिपोर्ट्स जो आई थीं उसका जब मेरे दफ्तर में लाये तो

मैंने एक फोटो लेली, मेरे निजी सहयोगी ने फोटो ली थी मुझे अभी बताया, मैंने कहा इसका ज़रा प्रिंट आउट ले लिया जाये | यह हैं फैलें जो quality defects निकलीं, यह सब quality defects की फैलें हैं जो मात्र उत्तर प्रदेश के काम की गुणवत्ता आप सबको दिखाती हैं |

हमारे संकल्प पत्र में स्पष्ट लिखा है, सभी किसानों को सरकार की और से एक नया energy efficient pump दिया जायेगा | इसको हमने जनता के सामने संकल्प के रूप में हमारी प्रतिबद्धता और यह मैं व्यक्तिगत अपनी भी संकल्प के रूप में उसको जोड़ता हूँ | साथ ही साथ एक बहुत ही दुखद घटना जो बिजली क्षेत्र में मेरे ढाई वर्ष के कार्यकाल लगभग तीन वर्ष होने आ रहे हैं, पूरे देश में मुझे एक मात्र अभी तक जांच आई है लेकिन यह जांच जब और किया जायेगा प्रदेश में तो मुझे लगता है शायद ऐसी और दुखद घटनाएं यहाँ मिलें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा | एक हमारे मान्य सांसद कुंवर सर्वेश कुमार जी, उन्होंने एक मुझे एक पत्र लिखा था कि उनके क्षेत्र मैं धर्म के आधार पे भेदभाव करके बिजली के कनेक्शन दिए जाते हैं | जो व्यवस्था है उसके हिसाब से मैंने राज्य सरकार को वह refer किया complain और कहा इसकी जांच की जाये, पहले तो राज्य सरकार ने लिख के दे दिया कि नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है सब ठीक-ठाक चल रहा है | फिर सांसद महोदय परेशान होक उन्होंने प्रधानमंत्री को complaint लिखी, अखिलेश यादव जी के खिलाफ उन्होंने मान्य श्री नरेन्द्र मोदी जी को 24 मई, 2016 को पत्र लिखा | और पत्र में बताया कि मुरादाबाद में कितना बुरा हाल है कैसे धर्म पे विद्युतीकरण के कनेक्शन दिए जाते हैं |

तब एक उच्च स्तरीय committee यहाँ पे भेजी गयी जिस committee की रिपोर्ट जब मैंने देखी तो मैं आपको भाइयो बहनों कैसे बताऊँ इतना दुःख हुआ कि क्या बुनयादी ढांचा जो एक आधारभूत बुनयादी सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराने

की हर सरकार का काम होता है उसमें भी जाति और धर्म पे भेदभाव होगा | और summary of findings यह रहीं -

Discrimination on religious grounds while implementation of the Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana. धर्म के आधार पे भेदभाव जब इस योजना को लागू किया गया |

.... मुफ्त में गरीबों के घर बिजली देनी चाहिए थी उनको बिजली देने के लिए पैसा माँगा गया | हमने राज्य सरकार को तुरंत आदेश दिया था कि वह FIR charge करे इस काम के बारे में अधिकारियों पे, contractor पे जिन्होंने इस प्रकार का भेदभाव किया है और पैसे का गलत इस्तेमाल किया है | और डिस्कॉम के ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और District Magistrate को कहा गया था कि वह एक District Electricity Committee की meeting बुलाके मान्य सांसद के साथ चर्चा करके इन सब विषयों को सुधार किया जाये | लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में लाख कोशिशों के बाद हम यहाँ के काम में सुधार, काम में गति और काम में ईमानदारी नहीं ला पारहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि क्यों महीने लग जाते हैं यहाँ पे काम को करने में, काम के अवार्ड में और फिर काम की गुणवत्ता क्यों ख़राब रहती है | पर ध्यान में आता है कि जब दो भ्रष्टाचारी पार्टीज मिलके इस प्रदेश के काम में लगेंगी फिर वह चाहे केंद्र की कांग्रेस और यहाँ की सपा हो तो आपने देख लिया किस प्रकार का काम हुआ | और आगे आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से एकदम ही बेबुनियादी गठबंधन, नैतिकता जिसमें किसी प्रकार की नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पे जिस गठबंधन की आधारशिला हो वह गठबंधन कैसे इस देश को संवार सकता है, कैसे इस देश को प्रगति और विकास से जोड़ सकता है मैं समझता हूँ यह सवाल जनता ज़रूर

इनको पूछेगी और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत, दो-तिहाई बहुमत की सरकार को विजयी बनाएगी, यह मेरा पूर्ण तरीके से विश्वास है |

धन्यवाद |

Q&A

Q. मेरा सवाल यह है मैंने संकल्प पत्र आपका पढ़ा है, पहले आप दो-तिहाई पर आप बहुमत बनायेंगे, मैंने पढ़ा है आपका संकल्प पत्र, उसमें आप उत्तर प्रदेश में कितनी बिजली पैदा करेंगे तो ज़रूरत के हिसाब से उसका कहीं उल्लेख नहीं है, कितनी बिजली कराएँगे ऐसा कहीं कुछ नहीं है |

A. वह इसलिए उल्लेख नहीं है कि बिजली के कारखाने में पहले तो जो कारखाने जैसे मैंने बताया घाटमपुर नोएडा के पास, उनको हमने .... कर लिया है और हमारा काम करने का ढंग यह है कि जब तक permissions नहीं हो local area में हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो ज़मीन की, पर्यावरण की तब तक घोषणा करने से इसमें लाभ नहीं है | लेकिन आज देश में इतनी पर्याप्त बिजली का हमारे पास संसादन है और हमने ट्रांसमिशन का जाल इतना फैला दिया है कि उत्तर प्रदेश को कभी एक दिन भी चौबीस घंटे बिजली देने में हमें कमी नहीं पड़ेगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार डबल इंजन जब तेज़ गति से चलेगी तो इस प्रदेश में कभी भी बिजली की कमी नहीं होने देगी |

Q. पियूष जी अभी आपने तमाम आंकड़े बताये विद्युत् पर खासतौर से और बिजली जो है वह किसी भी राज्य के लिए केंद्र और राज्य दोनों का विषय होता है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के घोषणा पत्र में यह चीज़ें हैं कि चौबीस घंटे बिजली दी जाएगी | पौने तीन साल का पूरा कार्यकाल आपका हो

गया और मैं और इसमें सवा-दो साल और जोड़ दे रहा हूँ 2019 तक उत्तर प्रदेश के लिए कितने पॉवर प्लांट केंद्र सरकार से सहयोग से या independently केंद्र सरकार कितने पॉवर प्लांट लगाने जा रही हैं? यह चीज़ें जनता जानना चाहती है?

A. ज़रूर | देखिये जैसा मैंने बताया घाटमपुर में काम शुरू हो गया है, जो काम मात्र पेपरों में था वह 1980 MW का project है वह काम शुरू हो गया है | नोएडा के नजदीक एक प्रोजेक्ट लगना था मेरे ख्याल से SJVM द्वारा है, मुझे कंपनी का नाम याद नहीं है, केंद्र सरकार की कंपनी लगा रही है | उसका ज़मीन पूरी ले ली गयी है, काम शुरू हुआ है उसके अप्रूवल का प्रोसेस शुरू हो गया है | केंद्र सरकार ने एक नयी निति घोषित की है उस निति के तहत जितने existing plants हैं उत्तर प्रदेश में वह सब plants अपनी capacity double कर सकते हैं बिना कोई further approval के | तो आज उत्तर प्रदेश में जितने existing plants हैं हम उन सबको डबल करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर पाएंगे, शुरू कर सकते हैं जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है, जैसे जैसे उपलब्धता ज़रूरत पड़ती है | और आज यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में कि अब कोयला भी हमारे काबू में है, कोयला भी दे दिया गया है राज्य सरकार को, बिजली घर भी शुरू भी हो गया है दो का काम | बाकी जितने यहाँ पे existing plants हैं उन सबको डबल करने का हमने पालिसी निर्धारित कर दी है और उसपे तेज़ी से काम किया जायेगा |

Q. पियूष जी मेरा सवाल है, आपने कहा था कि एक बार मीटिंग बुलाई थी दिल्ली में जब आपके पास सरप्लस बिजली थी आपने यह आरोप लगाया था कि दिल्ली की केन्द्रवासी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार आई ही नहीं आपसे बिजली लेने | तो मेरा यह कहना है, आपसे जानना है मेरे दो सवाल हैं, पहला सवाल यह है कि आपने कहा यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त बिजली की बिजली हमारे कोटे की मिली ही नहीं जो हम अपने रिसोर्स से पैदा किया वह हमने उत्तर

प्रदेश को दी | दूसरा सवाल था कि आप ही के प्रदेश के किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने एलईडी बल्ब दिए थे किसानों को मुफ्त में बांटने के लिए वह बल्ब को यहाँ के लोगों ने अधिकारियों ने मिलके मुफ्त में बाज़ार में बेच दिया, किसानों को नहीं मिला | इन दोनों सवालों का ज़रा सा जवाब दें |

A. जहाँ तक बिजली उपलब्ध कराने की बात है बाकी तो आप सबको याद होगा जब मैं नया नया मंत्री बना था पहले-दूसरे दिन ही यहाँ की सपा सरकार ने कुछ controversy बनाने की कोशिश की थी कि जैसे कोई दिल्ली ने बिजली काटी है | आपको फिर मैंने जानकारियां तभी भी दीं थी कि बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं ही छोड़ दी थी उसी दिन घंटों के भीतर हमने और बिजली sanction की क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब एक संकट का माहौल था | उसके 6-8 महीने, 9 महीने बाद फिर एक बार सपा सरकार ने टालने की कोशिश की कि केंद्र सरकार पे, तुरंत हमने बिजली आवंटन करी जो बिजली सपा सरकार ने खरीदी नहीं, हमारे आवंटन करने के बावजूद खरीदी नहीं | तीसरी बात, अब तो मैंने आपके समक्ष ही रख दिया अब तो केंद्र सरकार की आवंटन की ज़रूरत ही नहीं है, 2.85 रुपये में जब बिजली आपको चौबीसों घंटे मिल पाती है तो यह आवंटन का सवाल ही कहाँ उठता है | अभी जायें वह पॉवर एक्सचेंज में जितनी बिजली चाहिए खरीद लें, power purchase agreement निकाल के जितनी बिजली चाहिए आज उपलब्ध है | और दूसरी बात, यह बात तो स्पष्ट हो गयी कि यह झूठा आरोप लगाया जाता है, सही आरोप तो मैं लगा रहा हूँ कि राज्य सरकार को जितनी बिजली चाहिए केंद्र देने को आज भी तैयार है | राज्य सरकार भ्रमित करती है यहाँ की जनता को और हम जब बिजली आवंटन करते हैं तो खरीदती नहीं है | हमने जब बिजली पर्याप्त मात्रा में पॉवर एक्सचेंज में रख ली हैं और आप अपने मोबाइल अप्प में देखते रहिये, चौबीस घंटे देखिये और देखते रहिये कि बिजली कब नहीं मिलती है

| चौबीसों घंटे पॉवर एक्सचेंज में बिजली मिलती है सस्ती बिजली, अब सवा चार बजे हैं, अब 2.88 रुपये और सस्ती हो गयी, 2.88 रुपये में अब बिजली मिल रही है | और जहाँ तक LED bulbs का सवाल है, यहाँ के, लखनऊ के LED bulbs का काम शायद नीटू टीपू, इस नामक कुछ लोगों के हाथ में चला गया है और जब केंद्र सरकार ने बल्बों की कीमतें लगभग 88% कम की, जो कांग्रेस, इन की आज गठबंधन की पार्टी है सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, कांग्रेस जो केंद्र में 310 रुपये का 7W का बल्ब खरीदती थी आज नरेन्द्र मोदी सरकार केंद्र में 38 रुपये में 9W का बल्ब और बल्ब कौन दे रहा है 38 रुपये में - Philips, विश्व की सबसे बड़ी लाइटिंग कंपनी 38 रुपये में 9W का बल्ब दे रही है जो 310 में कांग्रेस, सपा कांग्रेस दोनों मिले जुले हैं, खरीदती थी | सोचो कितना भ्रष्टाचार और कैसे वह लोग काम करते थे, वैसे लखनऊ में क्यों यह नीटू टीपू को दिया जा रहा है यह काम यह आपने मुझे लगता है सपा को पूछना पड़ेगा | कुछ पत्रकारों की हंसी से ज़ाहिर होता है |

Q. जी मेरा सवाल यह है कि जो आप बता रहे हैं 2.85 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही है .... से, हमारे यहाँ जो बिजली निजी पॉवर प्लांट्स जो लगे हैं यूपी में उनसे खरीदी जाती है 6 रुपये .... इस की वजह से बहुत सारा घाटा पॉवर कारपोरेशन को लगातार को होता चला आ रहा है | मुश्किल यह है कि इन्होंने power purchase agreement उन निजी कंपनियों से कर रखे हैं और बिजली इनसे लेना मजबूरी हो गयी है | आपकी सरकार आएगी तो शायद आप को भी इस agreement को follow करना ही पड़ेगा, इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता है आपके पास?

A. देखिये यह बहुत दुर्भाग्य है कि यहाँ की राज्य सरकार ने इतने महंगे बिजली के power purchase agreements (PPAs) पहले से बनाके रखे हैं, जो लम्बे

अरसे के होते हैं, 20-25 वर्ष के PPA होते हैं और permanent बोझा राज्य सरकार हारने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता के कन्धों पे छोड़ के जा रही है | और उसकी निस्बत नरेन्द्र मोदी सरकार ने क्या किय राज्य के लिए? नरेन्द्र मोदी सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम अस्सुरांस योजना लागू कि जिस उदय योजना के तहत आज उत्तर प्रदेश को लगभग 2019-20 तक पूरे जो loss-making DISCOM है उसको profit में convert करने में हम मदद करेंगे | लगभग 33,400 करोड़ रुपये का लाभ राज्य को होगा अगले 3 वर्षों में, 33,400 करोड़ का लाभ राज्य को, उत्तर प्रदेश के DISCOMs को उदय योजना के तहत होगा | और 2020-21 के आगे 26,621 करोड़ का अनुमानित लाभ उत्तर प्रदेश को हर वर्ष होगा, 26,621 करोड़ हमारे उदय योजना के तहत | तो जो घाटा अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश की सरकार और जो भ्रष्टाचार मिलीभगत में कांग्रेस और सपा ने करके उत्तर प्रदेश को अँधेरे में रखा, भ्रष्टाचार से लिप्त रखा और विकास से वंचित रखा उसको पूरा करने के लिए मोदी जी की सरकार इस प्रकार के कार्यक्रम लाती है |

Q. पियूष जी मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके पास में अभी 73 सांसद हैं उत्तर प्रदेश से और आपने मुझे जहाँ तक याद है कि वाराणसी में कुछ ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था पिछले डेढ़-दो साल पहले जिसमें कि पॉवर लाइनों का restructuring की | But आपने वह जो भी किया वह वाराणसी में किया और आपके जो balance 72 सांसद हैं उनके क्षेत्र में कहीं कुछ नयी योजनाएँ नहीं आईं, एक तो यह है | दूसरा बात मेरा यह कहना है कि जो electricity bill है अभी जो एक normal consumer को मिलता है उसमें multiple surcharges paste होते हैं और जैसे कि आपने Telecom Regulatory Authority बना रखी है, क्या ऐसा संभव नहीं है कि आप बिजली के बारे में कुछ इस तरफ से कर पाएं?

A. बिजली के क्षेत्र में जैसा आप सब जानते हो भारत के संघीय ढांचे में पूरा काम राज्य सरकार के माध्यम से ही होता है | तो Integrated Power Development Scheme में हमने कुछ पैसा लगभग 5000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिया जिससे वह शहरी इलाकों में भी विद्युतीकरण को सुधार कर सके, उसकी व्यवस्था को सुधार कर सके | लेकिन primary responsibility और यह सुधार करने का काम राज्य सरकार के हाथों में ही होता है, राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी होती है | केंद्र से हम सिर्फ उसको supplement कर सकते हैं और वाराणसी एक प्राचीन शहर है, विश्व का सबसे पुराना शहर है, एक धार्मिक शहर है जिसमें उत्तर प्रदेश की और पूरे देश और विदेश में करोड़ों लोगों की आस्था जुडी हुई है | और मैं समझता हूँ पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो वहां पे सुधार हो विद्युतीकरण का जिससे पर्यटक आये, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में और गति हो, जिससे यहाँ पे नए नौकरी के स्वयं रोज़गार के अवसर हों, उसका एक मॉडल के रूप में केंद्र सरकार सहायता दे रही है, राज्य सरकार उसको काम को गति दे पाए उस काम के लिए | लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो और यह जो हजारों करोड़ 33,000 करोड़ अगले तीन वर्ष उसके बाद 2020-21 से 26,000 करोड़ हर वर्ष बचेंगे मैं समझता हूँ इस पैसे को इस्तेमाल करके पूरे देश में हर शहर में underground cabling जो वाराणसी में हो रही है वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में कर पाएंगे, क्यों नहीं आगरा, क्यों नहीं मेरठ, क्यों नहीं गाजीपुर, क्यों नहीं गोरखपुर, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में इस प्रकार की अच्छी व्यवस्था बने तब जाके उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था वास्तव में सुधर सकेगी, अच्छी बन पायेगी |

हाँ जहाँ तक बिजली के bills का सवाल है यह भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं | यह संघीय ढांचे में केंद्र सरकार बिजली के rate, tariff set नहीं कर सकती है वह राज्य सरकार petition file करती है और state regulator उस petition के

आधार पे तय करता है | हमने ..... में हम जो यहाँ पे बिजली के जितने घोटाले हो रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म करेंगे, बिजली के क्षेत्र में बचत करेंगे और उस बचत का सीधा लाभ जनता को दिया जायेगा | हम यहाँ उद्योग चाहते हैं जिससे उद्योग को भी प्रोत्साहन मिले और नए रोज़गार और स्वयं रोज़गार के अवसर मिले, कम सस्ती बिजली मिलेगी तो उद्योग भी आएगा, लघु उद्योग, बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश में आ पायेगा | साथ ही साथ किसानों को कम दरों पे बिजली देने का भी हमने निर्णय लिया है कि यह नयी सरकार यह काम भी करेगी कि कैसे हर घर तक को बिजली पहुंचाए, 100 unit तक मात्र 3 रुपये में बिजली हर गरीब को मिले और किसानों के भी बिजली के बिल कम हों उसके लिए चिंता की जाये और जैसा मैंने कहा energy efficient pump देके वैसे ही बिजली की खपत को भी किसानों की कम करके उनके बिजली के बिल कम किये जायें | हमारे कई अधिकारी कहते हैं कि जब वह जाते हैं गाँव में और पूछते हैं भाई आप बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं ले रहे हो तो तीन प्रमुख कारण बताये जाते हैं | एक तो यहाँ की रिशवतें जो मांगी जाती हैं कि रिशवत के बगैर कनेक्शन नहीं मिलता है दूसरा जो BPL नहीं है उनको माँगा जाता है अनाप-शनाप बिल दिया जाता है कि एक लाख रुपये लगेगा आपके घर में बिजली पहुँचाने के लिए, 50,000 रुपये लगेगा, और तीसरा कनेक्शन लेने के बाद इतनी बड़ी बिल आ जाती है कि व्यक्ति उसी में उसकी कमर टूट जाती है |

हमने निर्णय लिया है केंद्र में कि आगे हर एक को स्मार्ट मीटर दिया जायेगा और मैंने यह निर्धारित किया है पूरे देश भर के लिए, उत्तर प्रदेश में भी हम लागू करेंगे, हमारी भाजपा की सरकार लागू करेगी कि हर घर को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाये जिसमें टैम्पर-प्रूफ होगा और कोई अनाप-शनाप बिल का भोज उपभोक्ता पे नहीं पड़ेगा |

Q. गोयल जी आपने ज़िकर किया, मैं एक Japanese newspaper से हूँ, आपने ज़िकर किया कि प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख ऐसे घर हैं जिनमें बिजली का कनेक्शन नहीं है | क्या मैं जान सकती हूँ कि मोदी जी के क्षेत्र में भी कुछ ऐसे घर हैं जो बिजली से वंचित हैं?

A. स्वाभाविक है पूरे प्रदेश में यह स्थिति है और यह details मैं लेके आया हूँ, पूरे प्रदेश की हर district-wise details मेरे पास हैं | आपने वाराणसी का ज़िकर किया, मैं आपको वाराणसी का भी एक example के रूप में आपके समक्ष रखता हूँ और देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद क्योंकि संघीय ढांचे में राज्य सरकार ही दे सकता है बिजली का कनेक्शन | मैं दिल्ली से कनेक्शन नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने आपको भी असमर्थ पाता हूँ | आपको जानके हैरानी होगी कि बारहवी पंचवर्षीय योजना जो अगले महीने ख़त्म होने जा रही है, 12^{th} Plan में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वाराणसी में 84.61 करोड़ की राशि का आवंटन हुआ | लेकिन आजतक उसमें मात्र 21.45 करोड़, 25% ही इस्तेमाल हो पाया, यह राज्य सरकार की विफलता है पैसा होने के बावजूद काम नहीं कर पा रहे हैं | और देखिये हैरानी की बात मैं बताता हूँ वाराणसी में उनको 1187 गावों में intensive electrification करना था जिसको कहते हैं हर मजला टोला घर तक बिजली पहुंचानी थी, मात्र 311 गावों में intensive electrification हुआ है जो 26% है | और अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात, गरीब के घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का वाराणसी में 32,634 घरों में मुफ्त कनेक्शन देने की ज़िम्मेदारी दी और पैसा केंद्र ने आवंटन किया, 32,634 poor, BPL households के लिए |

अब जब मैं आंकड़ा सुनाऊंगा गरीब के लिए भी पैसा उपलब्ध होने के बावजूद मात्र 7,292 - 22% गरीब के घरों में 31 जनवरी, 2017 तक का आंकड़ा लाया हूँ, 8 दिन पुराना आंकड़ा लाया हूँ मैं भाइयो और बहनों, 31 जनवरी 2017 तक यह स्थिति है

वाराणसी की और इस प्रदेश के हर जिल्ले की स्थिति इसमें उपलब्ध है, जिसको जिस जिल्ले में इंटरेस्ट हो उसकी स्थिति मेरे सामने है |

Q. पियूष जी मेरा सवाल है, कि आपने power surplus की बात की, आपने industry की बात की, यहाँ उत्तर प्रदेश में 6 से 7 constituency ऐसे हैं, VIP constituency जहाँ चौबीस घंटे बिजली होती है और इस देश में .....

Ends.